ranging recommendations covering various aspects of customer services-Reserve Bank of India has since issued instructions to the banks to implement the accepted recommendations of die Committee-

रुग्णता की परिभाषा में संशोधन

186. श्री आत मोहम्मद :
चौधरी हरमोहन सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "रुग्णता" की परिभाषा में संशोधन करने संबंधी मामला सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस संबंध में कहां तक और किस स्तर पर कार्यवाही की गई है; और

(घ) "रुग्णता" की परिभाषा में संशोधन करने के कारण क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ) संभवत: माननीय सदस्य नायक समिति की सिफारिशों के अनुसरण में लघु उद्योग क्षेत्र में रुग्ण एककों की परिभाषा में परिवर्तन का उल्लेख कर रहे हैं। नायक समिति की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात, भारतं रिजर्व बैंक ने अप्रैल, 1993 में रुग्ण लघु उद्योग एककों की परिभाषा के बारे में अनुदेश जारी किये हैं। किसी लघु उद्योग एकक को रुग्ण एकक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, जब:--

(i) इसका कोई भी उधार खाता संदिग्ध शमिल हो गया हो, अर्थात् इसके किसी भी उधार खाते के संबंध में मूलधन अथवा ब्याज, छह वर्षों से अधिक की अवधि के लिये अतिदेय रहा ; और

(ii) गत दो लेखा वर्षों के दौरान उसकी अधिकतम शुद्ध मालियत में 50% अथवा उससे अधिक की सीमा तक संचयी नगद हानियों के कारण शुद्ध मालियत में कमी आई हो।

संशोधित परिभाषा से प्रारंभिक अवस्था में ही रुग्णता का पता लगाने और इस संबंध में उपचारी उपाय करने में सहायता मिलेगी।

Assistance to Maharashtra and Gujarat

187- SHRIMATI CHANDRKA ABHINANDAN JAIN: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the central assistance provided to the Maharashtra and Gujarat Government under die Minimum Needs Programme during the last three years, year-wise;

(b) whether there is a curtadmen' in the assistance to be given dun the current year;

(c) if so, die details of specific schemes for which the curtailment has been made; and

(d) the reasons for this curtailment in die assistance?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M-V-CHANDRASHEKHAR MURTHY): (a) The outlays under Minimum Needs Programme, though earmarked, form part of the State's Annual Plan Outlays- The Block Central assistance is provided to finance the Plan outlay as a whole and not related to a particular programme/scheme- As such Central assistance can not be identified with a particular or a Group of MNPs- The total outlay-under MNP is earmarked. When the State incurs less expenditure than the earmarked outlay, there is a proportionate cut in the Central assistance to the States- Details of outlays,